पीएफआरडीए ने नियमों को दी मंजूरी

प्रतिस्पर्धा और ग्राहक सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी

नई पेंशन योजना का विस्तार, वाणिज्यिक बैंकों को हरी झंडी

उभरती वास्तविकताओं, खुदरा और गिग-इकोनॉमी क्षेत्रों में बीमा सुरक्षा का विस्तार करने के उद्देश्य के साथ पीएफआरडीए ने पहली अप्रैल 2026 से पेंशन फंड के लिए निवेश प्रबंधन शुल्क संरचना को संशोधित किया है. संशोधित स्लैब-आधारित आईएमएफ में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए अलग-अलग दरें होंगी है. एमएसएफ कोष को अलग-अलग गिना जाएगा. कंपोजिट स्कीम के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों या स्वत- चयन और सक्रिय चयन और 100 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का वविकल्प चुनने वालों के लिए आईएमएफ समान रहेगा.

नई दिल्ली, 02 जनवरी. पेंशन विनियामक ने अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों को भी नयी पेंशन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से पेंशन कोष चलाने की छूट देने की तैयारी के साथ साथ एनएपीए के प्रोत्साहन के लिए प्रबंधनाधीन निधि का कुछ पैसा योजना के प्रचार प्रसार के लिए बिचौलिया इकाइयों की मदद को मंजूरी दी है.

वित्त मंत्रालय की गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को पेंशन कोष शुरू करने की छूट के नियमों को मंजूरी दे दी है. इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा और ग्राहक सुरक्षा मजबूत करना है. प्रस्तावित नये नियमों के तहत से पीएफआरडीए के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत समन्वित जागरूकता, पहुंच और वित्तीय-साक्षरता पहल का समर्थन करने के लिए एयूएम का 0.0025 प्रतिशत एनपीएस इंटरमीडियरीज -(बिचौलिया फर्मों) के संघ (एएनआई) को दिया जाएगा. पीएफआरडीए के नियामकीय सुधारों में वर्तमान बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है. अभी एनपीएस में बैंकों की भागीदारी सीमित थी. भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुरूप मजबूत बैंकों को ही पेंशन फंड प्रायोजित करने की अनुमति होगी. वित्त मंत्रालय का कहना है कि विस्तृत मानदंड अलग से अधिसूचित किए जाएंगे और नये तथा वर्तमान दोनों पेंशन फंडों पर लागू होंगे. इसके साथ ही एनपीएस ट्रस्ट के बोर्ड में तीन नये न्यासियों की नियुक्ति की गयी है. इनमें भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, यूटीआई एएमसी - ट्रस्टी की पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष स्वाति अनिल कुलकर्णी, डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के सह-संस्थापक और प्रमुख और सिडबी द्वारा प्रबंधित फंड ऑफ फंड्स स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यम पूंजी निवेश समिति के सदस्य डॉ. अरविंद गुप्ता शामिल हैं.

2000 रुपये के 98 .41 प्रतिशत नोट रिजर्व बैंक के पास वापस आये

मुंबई, 02 जनवरी. प्रचलन से बाहर किये गये 2000 रुपये के 98.41 प्रतिशत नोट अब तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास वापस आ गये हैं. केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को एक यह जानकारी दी. उसने बताया कि 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने की घोषणा 19 मई 2023 को की गयी थी. उस समय 3.56 लाख करोड़ मूल्य के ये नोट प्रचलन में थे. गत 31 दिसंबर 2025 को यह आंकड़ा घटकर 5,669 करोड़ रुपये रह गया है. इस प्रकार, 98.41 प्रतिशत नोट आरबीआई के पास वापस आ चुके हैं. 2000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा के बाद सात अक्टूबर 2023 तक इन नोटों को बैंक शाखाओं में जमा कराने या बदलवाने की सुविधा दी गयी.

निर्यातकों के लिए सरकार की बड़ी मदद

पहले महीने 3,100 करोड़ मंजूर, 8,599 करोड़ आवेदन आए

पहले ही महीने सैकड़ों एमएसएमई इकाइयों को राहत

नई दिल्ली, 02 जनवरी. केंद्र सरकार ने निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से लागू करने के बाद पहले महीने में 8,500 करोड़ रुपये से अधिक के आवेदन और 3,100 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृतियां प्रदान की हैं.

सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम क्षेत्र के निर्यातकों को नकदी,बाजार विविधीकरण और रोजगार संवर्धन में मदद देने के लिए यह योजना पहली दिसंबर 2025 से लागू की गयी है. इस योजना के तहत सरकार उन्हें अतिरिक्त ऋण सुविधा पर 100 प्रतिशत गारंटी की सुविधा प्रदान कर रही है. वित्तीय सेवा विभाग द्वारा क्रियान्वित सीजीएसई के तहत बैंक और वित्तीय संस्थान इस समय अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के दौरान भारतीय निर्यातकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है. यह योजना पात्र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्यातक एमएसएमई इकाइयों को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त, बिना जमानत कर्ज सहायता प्रदान करने के लिए है. वित्त मंत्रालय के अनुसार पहले महीने 31 दिसंबर तक कुल राशि 8,599 करोड़ रुपये की राशि के कर्ज के लिए 1,788 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 716 आवेदनों को 3,141 करोड़ रुपये की राशि के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है.

योजना के तहत निर्यातकों को उनके मौजूदा निर्यात ऋण/ कार्यशील पूंजी सीमा के 20 प्रतिशत तक के बराबर कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. योजना 31 मार्च तक या 20,000 करोड़ रुपये तक की गारंटी जारी होने तक (जो भी पहले हो) खुली रहेगी.

विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि 38 महीने के निचले स्तर पर

मुंबई, 02 जनवरी. नये ऑर्डरों में सुस्ती से विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि दर माह-दर-माह आधार पर दिसंबर में घटकर 38 महीने के निचले स्तर पर आ गयी.

एसएंडपी ग्लोबल द्वारा शुक्रवार को जारी एचएसबीसी भारतीय विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक रिपोर्ट में यह बात कही गयी है. भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का पीएमआई दिसंबर में घटकर 55 रह गया. यह दो साल से ज्यादा समय में विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में सबसे सुस्त वृद्धि को दर्शाता है. नवंबर में पीएमआई 56.6 रहा था. पीएमआई का 50 से ऊपर रहना गतिविधियों में वृद्धि को और इससे कम रहना गिरावट को दर्शाता है. इसका 50 का स्तर स्थिरता का द्योतक है. एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में इकोनॉमिक्स एसोसिएट डायरेक्टर पॉलियाना डी लीमा ने रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, वृद्धि की रफ्तार कम पड़ने के बावजूद भारतीय विनिर्माण उद्योग का प्रदर्शन 2025 में अच्छा रहा. हम वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसे में नये कारोबार में तेज वृद्धि के कारण कंपनियों के व्यस्त रहने की उम्मीद है.

वस्त्र मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आठ-नौ जनवरी को गुवाहाटी में

नई दिल्ली, 02 जनवरी. राज्यों के वस्त्र मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आठ से नौ जनवरी तक असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जायेगा. यह जानकारी केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने गुरुवार को दी. मंत्रालय ने कहा है कि दो दिन के इस सम्मेलन में देशभर के राज्यों के वस्त्र विभाग के मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. इस सम्मेलन का उद्देश्य नीतिगत समन्वय, क्षेत्रीय विकास तथा भारत के वस्त्र क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर चर्चा करना है. इस सम्मेलन के साथ ही वहां पूर्वोत्तर सम्मेलन (नॉर्थईस्ट कॉन्क्लेव) का आयोजन किया जाएगा, जिसका मुख्य फोकस पूर्वोत्तर क्षेत्र के वस्त्र क्षेत्र को सशक्त और मजबूत बनाना होगा.

सोने-चांदी के दामों में आई तेजी

1.34 लाख पार पहुंचा सोना

2.34 लाख तक पहुंची चांदी

नई दिल्ली, 02 जनवरी. सोने और चांदी के दामों में आज अचानक तेजी देखी गई है. 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 954 रुपए बढ़कर 1,34,415 और 1 किलो चांदी 5,656 बढ़कर 2,34,906 पर पहुंच गई.

तीन दिन की गिरावट के बाद यह तेजी निवेशकों के लिए राहत लेकर आई है. डॉलर की कमजोरी, रूस-यूक्रेन संघर्ष और वैश्विक मांग तेजी के प्रमुख कारण रहे. विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल सोने का भाव 1.50 लाख रुपए और चांदी 2.75 लाख तक जा सकता है. भारतीय घरों में सोने की कुल वैल्यू देश की लष्ठक्कसे भी अधिक हो गई है. सोने-चांदी के दामों में तीन दिन की गिरावट के बाद 2 जनवरी को तेजी देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 954 रुपए बढ़कर 1,34,415 और 1 किलो चांदी 5,656 बढ़कर 2,34,906 पर पहुंच गया.

दिसंबर 2025 में सोने का ऑल टाइम हाई

1,38,161 और चांदी 2,43,483 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया था. सोने में तेजी के पीछे डॉलर कमजोर होना, वैश्विक जियोपॉलिटिकल तनाव और चीन जैसे देशों की लगातार खरीदारी मुख्य कारण हैं. वहीं चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड, अमेरिकी टैरिफ के डर और मैन्युफैक्चरर्स की होड़ ने दाम बढ़ाए हैं. केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के अनुसार, चांदी की मांग में तेजी आगे भी बनी रहेगी और यह 2.75 लाख तक जा सकती है. सोने का भाव भी साल के अंत तक ?1.50 लाख प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच सकता है. सोना खरीदते समय हमेशा हॉलमार्क वाला सर्टिफाइड गोल्ड और सही कीमत का क्रॉस-चेक करना जरूरी है.

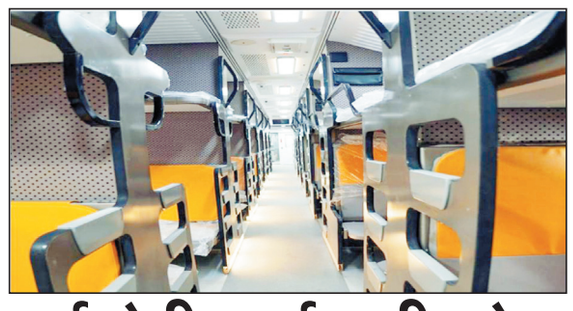

नई सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन में आधुनिक सुविधाएं

16 कोच और 823 यात्रियों की क्षमता के साथ सुरक्षा पर जोर

आराम, सुरक्षा और हाई-स्पीड का अनोखा संगम

नई दिल्ली, 02 जनवरी. देश में यात्रियों को तेज़ और सुरक्षित यात्रा का अनुभव देने के लिए नई सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन तैयार हो गई है. इसमें 16 कोच और 823 यात्रियों की क्षमता है. एर्गोनॉमिक बर्थ्स, स्वचालित दरवाजे, वेस्टिब्यूल्स, उत्कृष्ट सस्पेंशन और शोर कम करने वाली तकनीक इसे आरामदायक बनाती है.

सुरक्षा के लिहाज से कवच सिस्टम, इमरजेंसी टॉक-बैक और उन्नत ड्राइवर केबिन कंट्रोल्स शामिल हैं. साथ ही डिसइंफेक्टेंट तकनीक उच्च स्वच्छता सुनिश्चित करती है. यह ट्रेन 180 किमी प्रति घंटे की डिजाइन गति तक चलने में सक्षम है. नई सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन यात्रियों के लिए आधुनिक तकनीक और सुविधाओं के साथ तैयार की गई है.

कुल 16 कोचों में 11 तीन-तल वाली (3टी), 4 दो-तल वाली (2टी) और 1 प्रथम श्रेणी (1ऐसी) कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 823 यात्रियों की है. इस ट्रेन में आराम और सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है. एर्गोनॉमिक बर्थ्स बेहतर कुशनिंग के साथ डिजाइन किए गए हैं, वहीं स्वचालित दरवाजे और वेस्टिब्यूल्स सुचारु आवागमन में मदद करेंगे.

सुरक्षा के लिहाज से यह ट्रेन कवच सिस्टम, इमरजेंसी टॉक-बैक और उन्नत ड्राइवर केबिन कंट्रोल्स से लैस है. यात्रियों और स्टाफ की सुरक्षा प्राथमिकता बनी रहे, इसके लिए डिजाइन में एयरोडायनामिक बाहरी लुक और ऑटोमेटिक बाहरी दरवाजे शामिल हैं. स्वच्छता पर भी ध्यान दिया गया है और ट्रेन में डिसइंफेक्टेंट तकनीक लागू की गई है. इससे यात्रियों को संक्रमण मुक्त और सुरक्षित यात्रा का भरोसा मिलता है. ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति तक चलने में सक्षम है, जिससे लंबी दूरी के सफर का समय कम होगा. आधुनिक तकनीक, सुरक्षा और आराम के संगम के साथ यह ट्रेन देश में यात्रियों के लिए एक नया अनुभव लेकर आएगी.

शेयर बाजारों में तेजी, सेंसेक्स 573 अंक उछला

मुंबई, 02 जनवरी. विदेशों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को तेजी रही और बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 573.41 अंक (0.67 प्रतिशत) की बढ़त में 85,762.01 अंक पर बंद हुआ. बाजार में आज शुरू से ही तेजी रही.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 182 अंक यानी 0.70 प्रतिशत ऊपर 26,328.55 अंक पर पहुंच गया. चौतरफा लिवाली के बीच 01 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट-बीड़ी तथा अन्य तंबाकू उत्पादों पर उपकर और कर बढ़ाने की अधिसूचना के बाद एफएमसीजी कंपनी आईटीसी के शेयरों में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही. इसका शेयर आज पौने चार प्रतिशत टूट गया. मझौली और छोटी कंपनियों के सूचकांक भी बढ़त में रहे. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.94 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.72 प्रतिशत चढ़ा. एफएमसीजी को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों में तेजी रही. रियलिटी, धातु, ऑटो, वित्त, बैंकिंग और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद समूहों की कंपनियों में लिवाली ज्यादा रही. एनटीपीसी का शेयर चार प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा. ट्रेंट में ढाई फीसदी से अधिक की तेजी रही. बजाज फाइनेंस, पावरग्रिड, मारुति सुजुकी, भारतीय स्टेट बैंक, बीईएल, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनीलिवर और एचडीएफसी बैंक के शेयर एक से दो प्रतिशत की बीच चढ़े.

चावल, चीनी, दालों में तेजी गेहूं, खाद्य तेलों के भाव टूटे

नई दिल्ली, 02 जनवरी. घरेलू थोक जिंस बाजारों में शुक्रवार को चावल के औसत भाव बढ़ गये. चावल के साथ चीनी और दालों में भी तेजी रही जबकि गेहूं और खाद्य तेलों में गिरावट का रुख रहा. औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत पांच रुपये बढ़कर 3,823 रुपये प्रति क्विंटल हो गयी. गेहूं तीन रुपये प्रति क्विंटल सस्ता हुआ और 2,853 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बोला गया. आटा छह रुपये महंगा हुआ. दाल-दलहनों में तेजी रही. तुअर दाल औसतन 107 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई.

मार्च के अंत से तीन साल में एक बार होगा निदेशकों का केवाईसी

नई दिल्ली, 01 जनवरी. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनियों के निदेशकों को एक बड़ी राहत देते हुए वार्षिक केवाईसी (पहचानों अपने ग्राहक को) की जगह तीन वर्ष में एक बार संक्षिप्त केवाईसी की व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है.

मंत्रालय की गुरुवार को जारी एक के अनुसार नयी व्यवस्था 31 मार्च 2026 से लागू होगी. इस मामले में परामर्श और चर्चा का यह निर्णय गैर-वित्तीय विनियामक सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है. कंपनियों (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के नियम 12क में किये गये संशोधन को बुधवार 31 दिसंबर 2025 को अधिसूचित किया गया. संशोधित सरल केवाईसी फॉर्म का उपयोग केवाईसी की शर्तों के अनुपालन के साथ-साथ निदेशकों के मोबाइल नंबर, ईमेल पता, आवासीय पता अपडेट करने और निदेशक पहचान संख्या (डिन) को पुन: सक्रिय करने के लिए किया जा सकेगा.

समाचार विशेष

योगी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की तैयारी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. मुख्यमंत्री आवास पर हुई कोर कमेटी की मैराथन बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दिल्ली रवाना हो गए हैं. माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद सरकार और संगठन में 'अदला-बदली' के फॉर्मूले पर अमल किया जाएगा.

मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर करीब डेढ़ घंटे तक चली कोर कमेटी की बैठक में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर गहन मंथन हुआ. इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री और आरएसएस के पदाधिकारियों की मौजूदगी में यह संकेत दिए गए कि संगठन के कुछ पुराने चेहरों को सरकार में लाया जा सकता है, जबकि वर्तमान मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. सूत्रों के अनुसार, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के सरकार में शामिल होने की प्रबल संभावना है.

मंत्रिमंडल में रिक्तियां और नए चेहरों को मौका- वर्तमान में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 54 मंत्री शामिल हैं, जबकि संवैधानिक नियमों के अनुसार यह संख्या अधिकतम 60 तक हो सकती है. हालिया लोकसभा चुनावों के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे जितिन प्रसाद और राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि के सांसद बनने से दो महत्वपूर्ण पद रिक्त हुए हैं.

2027 का लक्ष्य : क्षेत्रीय और जातीय संतुलन

इस पूरे फेरबदल का मुख्य केंद्र 2027 का विधानसभा चुनाव है. पार्टी के भीतर यह माना जा रहा है कि वर्तमान में पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व अधिक है, इसलिए आगामी विस्तार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं को आगे लाकर क्षेत्रीय संतुलन बनाया जाएगा. इसके अलावा, विभिन्न आयोगों और बोर्डों में खाली पड़े पदों को भी जल्द भरने पर सहमति बनी है. पंकज चौधरी अब दिल्ली में हाईकमान के सामने कोर कमेटी के इन प्रस्तावों को रखेंगे, जिसके बाद अंतिम मुहर लगेगी. यह पूरी कवायद न केवल प्रशासनिक रिपोर्टों और एसआईआर के आकलन पर आधारित होगी, बल्कि इसमें जातीय समीकरणों को भी पूरी तरह साधा जाएगा.

नितिन नबीन नहीं जाएंगे राज्यसभा!

अमित शाह और गडकरी वजह

नई दिल्ली. इस समय बिहार की राजनीति राज्यसभा की खाली होने वाली 5 सीटों को लेकर काफी सुर्खियों में है. यह चर्चा खासकर इस बात को लेकर है कि भाजपा इस बार 2 सीटों पर किसे भेजेगी?

नितिन नबीन जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने तो चर्चा परवान चढ़ रही थी कि 1 सीट पर तो वही जाएंगे. भाजपा सूत्रों के अनुसार नितिन नबीन राज्यसभा नहीं भेजे जा सकते हैं. इसकी वजह भी है. इसके पहले भी कई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जो विधायक रहकर कई वर्ष तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे. भाजपा के जाने माने चेहरों में से एक नितिन गडकरी हैं. ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के सदस्य से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय कर चुके हैं. नितिन गडकरी भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाज रानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री रहे हैं. इससे पहले 2010 से लेकर 2013 तक वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे. 52 वर्ष की आयु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले वे इस पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी थे. नितिन गडकरी एक जनवरी 2010 से 22 जनवरी 2013 तक अध्यक्ष रहे. इस बीच वे वर्ष 2008 में वे अंतिम बार विधान परिषद चुने गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के समय वे विधान परिषद सदस्य थे. और ये वर्ष 2014 में नागपुर लोकसभा से चुनाव जीत कर आए थे.

सहकारिता मंत्री भी रहे हैं शाह

इसके अतिरिक्त शाह जुलाई 2021 से पहले सहकारिता मंत्री भी रहे. वे 2014 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के अध्यक्ष भी रहे हैं.

शाह भाजपा अध्यक्ष रहते हुए विधायक रहे

22 अक्टूबर 1964 को जन्मे अमित अनिल चंद्र शाह गृह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2014 से 2020 तक भारतीय जनता पार्टी के 10वें अध्यक्ष के रूप में काम किया है. इस दौरान वे गुजरात के नरनपुरा विधानसभा से विधायक थे. शाह विधायक और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर 2012 से लेकर 2017 तक बने रहे. यानी करीब तीन साल बाद वे विधायक रहकर भी भाजपा के अध्यक्ष बने रहे.

हेमांग जोशी अब गुजरात में नए पोस्टर ब्वॉय

अहमदाबाद. लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने तत्कालीन सांसद रंजनबेन भट्ट को चुनाव मैदान में उतारा था लेकिन उन्हें जब तीसरी बार टिकट मिलने का विरोध हुआ तो बीजेपी को टिकट काटना पड़ा. ऐसे में वडोदरा नगर निगम के आधीन आने वाले नगर प्राथमिक समिति की उपाध्यक्ष हेमांग जोशी की लॉटरी लग गई थी. चूंकि वडोदरा गुजरात में बीजेपी का अभेद्य गढ़ है. ऐसे में हेमांग जोशी की जीत टिकट मिलते ही तय हो गई थी.

यही वजह थी कि चुनाव नतीजे आने से पहले ही उनके कार्यालय का निर्माण भी शुरू हो गया था. अब जब गुजरात में बीजेपी ने नई टीम का ऐलान किया, तो हेमांग जोशी राजनीति के नए धुरंधर बनकर उभरे हैं. मंगलवार को वह युवा मोर्चे का दायित्व संभालने के बाद पहली बार गांधीनगर स्थित कमलम् में बैठे. गुजरात की राजनीति में जितनी तेजी से हेमांग जोशी के उदय हुआ है. उतना शायद किसी और नेता का हाल के सालों में हुआ होगा. अभी तक गुजरात में बीजेपी के सर्वाधिक लोकप्रिय और युवा चेहरा हर्ष संघवी माने जाते थे. बिहार चुनावों के दौरान पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया था. 34 साल के हेमांग जोशी अब गुजरात में नए पोस्टर ब्वॉय बन गए हैं.

पोरबंदर से आए थे वडोदरा- हेमांग जोशी मूलरूप से पोरबंदर के रहने वाले हैं. 2008 में उनकी फिजियोथेरेपी की पढ़ाई के लिए उनके पिता ने जब वडोदरा का रुख किया तो इसके बाद हेमांग जोशी ने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के छात्र बने. वह 2008 से लेकर वह 2021 वडोदरा की एमस यूनीवर्सिटी में ही रहे.

हेमांग जोशी को किसका आशीर्वाद?

तीन साल में शिक्षण समिति के उपाध्यक्ष से सांसद और गुजरात में बीजेपी के युवा चेहरे बने हेमांग जोशी की तेज तरक्की को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उन्होंने सांसद बनने के बाद केंद्रीय नेतृत्व को प्रभावित किया है. यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है. जोशी के जबरदस्त प्रमोशन के पीछे राम माधव से उनकी नजदीकी की भी चर्चा है. कुछ विश्लेषक कहते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के काफी निकट हैं. जोशी की तरक्की में वैष्णव संप्रदाय के महाराज व्रजराज कुमार महोदय के समर्थन और आशीर्वाद होने की चर्चा है.

विशेष | **एक पंचायत चुनाव में लेफ्ट को हराना था**

भाजपा और कांग्रेस ने ही कर लिया गठबंधन

तिरुवनंतपुरम. केरल का निकाय चुनाव लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है. सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रैटिक फ्रंट को झटका लगा है तो विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रैटिक फ्रंट नतीजों से गदगद है.

भारतीय जनता पार्टी भी खुश है क्योंकि उसके वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है और तिरुवनंतपुरम में वह अपना मेयर बनाने में कामयाब रही है. अब एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. त्रिशूर जिले की ग्राम पंचायत में लेफ्ट को हराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने ही हाथ मिला लिया. कांग्रेस के सदस्यों ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया और बीजेपी के लोगों ने मिलकर एक पूर्व कांग्रेसी को पंचायत अध्यक्ष चुन लिया. इस तरह की घटना के बाद केरल के सीएम पिनराई विजयन ने इसकी शिकायत कांग्रेस नेतृत्व से कर डाली है.

यह मामला त्रिशूर जिले की मत्तातुर पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव का है. अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने बगावत कर दी और बीजेपी के साथ चले गए. दूसरे तरफ से कांग्रेस के और बागी लेफ्ट के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे. फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते लेफ्ट ने फिर से कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है. इस मामले पर कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए सीएम पिनराई विजयन ने एक पोस्ट में लिखा है, मत्तातुर पंचायत में जो हुआ वह एक शातिराना ट्रेंड दिखा रहा है. कांग्रेस के लोग सत्ता के लिए बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं. दलबदल की यह राजनीति आखिर में संघ परिवार के उस प्रोजेक्ट को सामान्य बना रही है जिसमें पाला बदलने और लोकतांत्रिक परिणाम को पलटने को सही माना जाता है. ऐसा ही पहले अरुणाचल प्रदेश, गोवा और पुडुचेरी में देखा गया और इससे केरल में बीजेपी की महत्वाकांक्षा को मदद मिल रही है. इस खतरनाक बदलाव पर कांग्रेस नेतृत्व को स्पष्ट शब्दों में जवाब देना चाहिए.